मप्र में सात पटवारियों की सेवा समाप्ति संघ अध्यक्ष सहित चार सस्पेंड

स्वामित्व योजना में 'जीरो वर्क' और काम से इनकार पड़ा भारी!

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्य में शून्य प्रगति दर्ज कराने, अपने हल्के में न रहने और असहयोग का रवैया अपनाने पर देवास जिले में ३ परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।

देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सोनकच्छ तहसील के घिचलाय में पदस्थ नितिन विश्वकर्मा, देवास ग्रामीण के अजय नागर और टोंकखुर्द के विशाल टईया को एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा से पृथक करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन तीनों को फरवरी २०२४ में ३ वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था। जांच और अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन में सामने आया कि ये पटवारी अपने हलके में निवास नहीं कर रहे थे, समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे थे और बीते ६ माह में इनकी राजस्व वसूली भी अत्यधिक असंतोषजनक पाई गई।

दूसरी ओर गुना जिले में भी 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-२०२६' में निर्धारित काम न करने और घोर लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गुना जिले में इस योजना के तहत अब तक एक भी रजिस्ट्री न होने के कारण जिले की रैंकिंग मध्य प्रदेश में फिसलकर ५४वें स्थान पर पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने ४ पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसमें जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र किरार भी शामिल हैं।

इनके अलावा निलंबित होने वाले पटवारियों में ललित मोहन शर्मा, तहसील बमौरी, विजय सिंह भील, तहसील कुंभराज और मेहरबान भील, तहसील मकसूदनगढ़ शामिल हैं। वहीं ४ ट्रेनी पटवारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

काम का विरोध और रजिस्ट्री न करने की जिद पड़ी भारी

दरअसल पटवारियों ने १५ सितंबर को जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपकर स्वामित्व योजना के तहत काम करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। पटवारियों का कहना था कि वे काम से पीछे नहीं हट रहे हैं लेकिन योजना में रजिस्ट्री का काम करने पर किसी भी गड़बड़ी या कार्रवाई की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाएगी। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की निरंतर अवहेलना और एसडीएम द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद कलेक्टर्स ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों और परिवीक्षा संबंधी शर्तों के तहत यह कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में साल में तीन बार ही केस की तारीख बढ़वा सकेंगे वकील

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अब वकील किसी मामले की सुनवाई की तारीख बार-बार आगे नहीं बढ़वा सकेंगे। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन करते हुए तारीख बढ़ाने की सीमा तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार, किसी मामले में सालभर के दौरान अधिकतम तीन बार ही सुनवाई की तारीख बढ़ाई जा सकेगी। यदि कोई अधिवक्ता किसी विशेष परिस्थिति या अवधि में अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसे रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन देना होगा। वहीं, सूचीबद्ध मामलों में कम से कम तीन दिन पहले स्थगन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। रजिस्ट्रार एक मामले में तारीख को केवल एक माह आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकेंगे। सात साल से अधिक पुराने मामलों में तारीख आगे बढ़ाने का प्रावधान नहीं होगा। नए नियमों के तहत अधिवक्ताओं के लिए ई-मेल, मोबाइल नंबर और व्हाट्सऐप नंबर दर्ज कराना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि उन्हें सभी सूचनाएं समय पर मिल सकें।

'एक लाख नौकरियां देंगे तो विभाग, पद और समयसीमा बताएं'

पटवारी ने रोजगार-भर्ती के रोडमैप से लेकर पेपर लीक और कर्ज तक सरकार को घेरा

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यूथ कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला। रोजगार, सरकारी भर्ती, युवा नीति, परीक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण, कर्ज और यूथ कॉन्क्लेव के आयोजन को लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार की पटवारी नहीं सुनते, वो खटारा नहीं तो क्या है? पटवारी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं का जमीन पर क्या परिणाम निकलेगा, इसका स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री की अगले साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये नौकरियां किन विभागों में, कितने पदों पर और किस समयसीमा में दी जाएंगी।

पटवारी ने कहा कि सरकार पहले ढाई लाख और फिर पांच लाख रोजगार देने की बात कर चुकी है। अब एक लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार को विभागवार रिक्त पदों की सूची, भर्ती का कैलेंडर और नियुक्तियों की समयसीमा सार्वजनिक करनी चाहिए। केवल रोजगार का आंकड़ा बताने से युवाओं की समस्या हल नहीं होगी। पटवारी ने रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवा पंजीकृत हैं, तब एक लाख रोजगार के बाद बाकी युवाओं के लिए सरकार की क्या योजना है, यह भी बताया जाना चाहिए। पीएससी की परीक्षा साल में दो बार कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी पटवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सिर्फ परीक्षा की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी और परीक्षा से नियुक्ति तक की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी। उन्होंने पिछली परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियों में हुई देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं को परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया की समयसीमा मिलनी चाहिए।

तीन लाख शिक्षक पद खाली होने का दावा

पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि स्कूल-कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली हैं। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों में भी पद रिक्त हैं और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवा वर्ष की बात की है, लेकिन युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े शिक्षा और रोजगार के सवालों का समाधान किए बिना केवल आयोजन करने से स्थिति नहीं बदलेगी।

पेपर लीक पर भी सरकार से जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा की पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए पटवारी ने कहा कि युवा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने व्यापमं का नाम बदलने के बावजूद परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद खत्म नहीं होने का आरोप लगाया। पटवारी ने परीक्षा संबंधी मामलों में कार्रवाई और उसके बाद होने वाली नियुक्तियों पर भी सरकार से जवाब मांगा।

'ये राहुल गांधी के नहीं, छात्रों के सवाल'

पटवारी ने इंदौर में कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं ने वहां जो सवाल उठाए, वे राहुल गांधी के व्यक्तिगत सवाल नहीं हैं। ये प्रदेश के छात्रों और युवाओं के सवाल हैं। उन्होंने रोजगार, शिक्षक भर्ती, हॉस्टल, सरकारी पदों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा। पटवारी ने यूथ कॉन्क्लेव की प्रकृति पर तंज कसते हुए कहा यह कॉन्क्लेव नहीं था, अपने खुद के करियर में चार चांद लगाने का प्रयास था।

युवती के बाल खींचकर बाहर निकालने का आरोप

पटवारी ने यूथ कॉन्क्लेव में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में एक युवती के बाल खींचकर उसे बाहर निकाला गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए यह फिलहाल पटवारी के आरोप के रूप में ही सामने आया है।

रोजगार मेलों के खर्च का भी हिसाब मांग लिया

पटवारी ने सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार मेलों के आयोजन में सरकारी संसाधन खर्च किए जाते हैं, लेकिन इनसे वास्तव में कितने युवाओं को रोजगार मिला, इसका स्पष्ट आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार से रोजगार मेलों पर हुए कुल खर्च और उनसे हुई वास्तविक नियुक्तियों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।

शिक्षकों के पेंशन मामले में कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी सरकार

हाईकोर्ट ने संविलियन को नई नियुक्ति नहीं माना, पुरानी सेवा गिनकर ओपीएस देने के निर्देश, तीन महीने बाद भी आदेश का अमल नहीं, अब रिव्यू की तैयारी

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में करीब ८० हजार शिक्षकों की पुरानी पेंशन का मामला अब सरकार और कर्मचारियों के बीच प्रशासनिक विवाद से निकलकर कानूनी टकराव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पूर्व शिक्षाकर्मियों की सेवा को निरंतर मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश के करीब तीन महीने बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका पालन नहीं किया है। इसके बजाय अब सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए रिव्यू याचिका और आगे डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है।

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने वर्ष २०१८ के संविलियन को नई नियुक्ति मानने के शासन के तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में शामिल होना सेवा का नया प्रारंभ नहीं, बल्कि संविलियन और पदनाम परिवर्तन की प्रक्रिया थी। ऐसे में उनकी पूर्व सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

१९९८ की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद

मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति २२ अगस्त १९९८ को जिला पंचायत के माध्यम से शिक्षाकर्मी वर्ग-२ के पद पर हुई थी। बाद में पंचायत अध्यापक संवर्ग नियम, २००८ के तहत वे अध्यापक और फिर वरिष्ठ अध्यापक बने। इसके बाद १५ फरवरी २०१९ को उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ किया गया। विवाद तब पैदा हुआ, जब शासन ने वर्ष २०१८ के सेवा भर्ती नियमों के नियम १८.१ और १८.२ का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को नई नियुक्ति माना और पूर्व सेवा को पेंशन के लिए स्वीकार नहीं किया। इसी आधार पर संबंधित कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के दायरे में रखा गया।

कोर्ट ने कहा- सेवा में ब्रेक नहीं तो नई नियुक्ति कैसे?

हाईकोर्ट ने शासन के इस तर्क को खारिज करते हुए २००८ के अध्यापक संवर्ग नियमों के नियम ५ का हवाला दिया। कोर्ट के मुताबिक शिक्षाकर्मियों को अध्यापक संवर्ग में शामिल किया जाना संविलियन था। जब कर्मचारी की सेवा में एक दिन का भी व्यवधान नहीं आया, तो केवल संवर्ग और पदनाम बदलने से इसे नई नियुक्ति नहीं माना जा सकता। अदालतने पेंशनके लिए संविलियनसे पहले की सेवा अवधि को भी जोडऩे और पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।

आदेश के बाद भी लागू नहीं हुआ फैसला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार पेंशन संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। लेकिन करीब तीन महीने गुजरने के बावजूद विभाग ने आदेश पर अमल नहीं किया है। अब विभाग की ओर से फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। मामले को लेकर ५ अक्टूबर को जबलपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ बैठक भी प्रस्तावित की गई, जिसमें आगेकी कानूनी रणनीतिपर चर्चाकी जानी है।

सरकार के सामने ८० हजार कर्मचारियों का सवाल

इस मामले का असर उन करीब ८० हजार शिक्षकों और संविदा शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिनकी नियुक्ति प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई थी। एनपीएस की जगह ओपीएस लागू होने पर सरकार को इन कर्मचारियों की पुरानी सेवा को पेंशन लाभ के लिए जोडऩा पड़ेगा। इससे राज्य के पेंशन व्यय पर बड़ा वित्तीय असर पडऩे की आशंका है। यही वित्तीय दायित्व अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। एक ओर कोर्ट का आदेश है, दूसरी ओर उसके अनुपालन से बढऩे वाला दीर्घकालिक वित्तीय भार। ऐसे में विभाग सीधे आदेश लागू करने के बजाय पहले न्यायिक विकल्प तलाश रहा है।

जबलपुर से मंडला जा रही बस खड़ी ट्रवसे टकरायी, बच्ची सहित तीन घायल

देर रात टिकरिया थाना क्षेत्र में हादसा

जबलपुर, (एजेंसी)। जबलपुर नेशनल हाईवे-३० पर टिकरिया थाना क्षेत्र के भावल के पास कल मंगलवार की देर रात जबलपुर से मंडला जा रही यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत तीन यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही डायल-११२ की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे-३० पर टिकरिया थाना क्षेत्र के भावल के पास जबलपुर से मंडला आ रही खेरावाली बस क्रमांक एमपी २० पीए ०६८७ मौके पर सडक किनारे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टिकरिया थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर चार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके साथ ही बस में सवार बाकी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। फिलहाल, हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। टिकरिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पकड़ा गया संदिग्ध पाकिस्तानी नहीं निकला

पुलिस जांच में आयी असली पहचान, युवक हरदोई निवासी शिवम पाठक निकला

जबलपुर, (एजेंसी)। शहर में बुधवार की सुबह व्हीकल फैक्ट्री के पास संदिग्ध हालत में मिले एक युवक को लेकर उस समय हड़कंप मच गया, जब सोशल मीडिया पर उसके पाकिस्तान के रावलपिंडी का निवासी होने का दावा तेजी से वायरल होने लगा। स्थानीय लोगों ने युवक को संदिग्ध अवस्था में देखकर उसे पकड़ लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद युवक को रांझी पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मामले की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर युवक को लेकर तरह-तरह की बातें प्रसारित होने लगीं। कुछ पोस्ट में युवक को पाकिस्तान का रहने वाला बताया गया, जबकि उसके कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने का दावा भी किया गया। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने युवक से पूछताछ कर उसकी पहचान और उसके बारे में जानकारी जुटाई।

पुलिस जांच में सामने आई नई पहचान

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि जांच के बाद युवक की पहचान शिवम पाठक, निवासी हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक युवक मानसिक रूप से कमजोर है और पूछताछ के दौरान अपनी पहचान को लेकर अलग-अलग जानकारी दे रहा था। इसी वजह से शुरुआत में उसकी पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी। पुलिस ने युवक के परिवार से भी संपर्क किया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार युवक पहले भी कई बार घर से बिना बताए घर से भाग चुका है। पुलिस की जांच में उसके पाकिस्तान से संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।

'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे की भी पुष्टि नहीं

युवक के कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने संबंधी दावे की भी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। रांझी टीआई उमेश गोल्हानी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संवेदनशील मामले में बिना तथ्य और पुलिस की पुष्टि के सोशल मीडिया पर जानकारी साझा न करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मानना उचित नहीं है। ऐसे मामलों में अफवाह फैलने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। पुलिस द्वारा युवक की पहचान और पूरे मामलेको लेकर आवश्यक जांचकी जा रही है।

बागेश्वर धाम के पास किशोरी से दुराचारके मामले में हाईकोर्ट सख्त

एसआईटी करेगी जांच; दो माह में मांगी रिपोर्ट

जबलपुर, (ईएमएस)। छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पास किशोरी से कथित दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने आरोपी राजू जाटव की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए छतरपुर पुलिस अधीक्षक को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी को यह पता लगाने को कहा गया है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किसने किया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का जैविक पिता कौन है। अदालत ने जांच पूरी कर दो माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी का दिया तर्क

शिवपुरी निवासी राजू जाटव की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी में दावा किया गया कि जिस स्थान को कथित घटनास्थल बताया गया है, वहां २४ घंटे पुलिस की निगरानी रहती है। ऐसे में वहां बताए गए तरीके से अपराध किया जाना संभव नहीं है। आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि किशोरी के गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए उसके डीएनए से मेल नहीं खाया है।

किशोरी ने अदालत में आरोपी पर आरोप से किया इनकार

मामले में सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि ट्रायल कोर्ट में गवाह के रूप में पेश हुई किशोरी ने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। जिरह के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी राजू जाटव ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। हाईकोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जब किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है और आरोपी के खिलाफ आरोप से वह स्वयं इनकार कर रही है, तो वास्तविक आरोपी का पता लगाना जरूरी है।

पहले आरोपी पर लगाए थे आरोप

अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि किशोरी ने पहले आरोपी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसके अलावा आरोपी की पत्नी की निशानदेही पर किशोरी को बरामद किए जाने की बात भी रिकॉर्ड पर है। इन परिस्थितियों और मामले में सामने आए विरोधाभासी तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दूसरी बार जमानत देने से इनकार कर दिया।

डीएनए जांच से भी नहीं हुआ आरोपी का मिलान

आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए उसके डीएनए से मेल नहीं हुआ है। इसके बावजूद अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर नहीं की। अब एसआईटी को पूरे घटनाक्रम की नए सिरे से पड़ताल करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और डीएनए संबंधी तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

दो माह में हाईकोर्ट को देनी होगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने छतरपुर एसपी को एसआईटी गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति और बच्चे के जैविक पिता की पहचान करना होगा। एसआईटी को अपनी जांच पूरी कर दो महीने के भीतर रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता नमन मिश्रा ने पक्ष रखा।

दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

राजू जाटव की पहली जमानत अर्जी ३० जून २०२६ को खारिज हो चुकी थी। दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया।

कटंगी की घटनाके बाद जिलेभरकी एंबुलेंस जांच के घेरे में

बीएमओ से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, सरकारीके साथ निजी आपातकालीन वाहनोंका भी जुटाया जा रहा डाटा

जबलपुर, (एजेंसी)। कटंगी क्षेत्र में पांच वर्षीय बच्ची को रेफर करते समय एंबुलेंस का टायर फटने और दूसरी एंबुलेंस के समय पर उपलब्ध नहीं होने की घटना ने जिले की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित सभी सरकारी और गैर-सरकारी आपातकालीन वाहनों की वास्तविक स्थिति की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के अनुसार विभाग निजी आपातकालीन वाहनों का भी पूरा डाटा जुटा रहा है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एंबुलेंस के दस्तावेज, तकनीकी स्थिति और जीवनरक्षक उपकरण निर्धारित मानकोंके अनुरूप हैं या नहीं।

टायर, ब्रेक से लेकर ऑक्सीजन सिस्टम तक होगी जांच

जांच के दौरान प्रत्येक एंबुलेंस का वैध बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र देखा जाएगा। इसके साथ ही टायरों की स्थिति और ग्रिप, ब्रेक, स्टेयरिंग तथा वाहन की नियमित सर्विसिंग का रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। एंबुलेंस के भीतर मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी पड़ताल होगी। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का दबाव, वेंटिलेटर, पोर्टेबल स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार किट और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता शामिल है। वाहनों में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ की तकनीकी दक्षता और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, चालकों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा एंबुलेंस संचालक और अस्पताल के बीच हुए अनुबंध की भी जांच की जाएगी।

१०८ सेवा की १००२ एंबुलेंस, फिर भी रिस्पांस टाइम पर सवाल

मध्यप्रदेश में संजीवनी १०८ सेवा के तहत १००२ एंबुलेंस संचालित होने का दावा है। इनमें १६७ उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस और ८३५ बेसिक जीवन रक्षक एंबुलेंस शामिल हैं। निर्धारित मानकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में २५ मिनट और शहरी क्षेत्रों में १८ मिनट के भीतर एंबुलेंस पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कटंगी की घटना ने इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एंबुलेंस का रास्ते में खराब होना और उसके विकल्प के समय पर उपलब्ध नहीं होने से यह स्पष्ट हुआ है कि केवल वाहनों की संख्या पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित रखरखाव और आपात स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।

औचक निरीक्षण की जरूरत

स्वास्थ्य विभाग की जांच में यदि वाहनों की फिटनेस, उपकरणों या दस्तावेजों में खामियां सामने आती हैं तो संबंधित संचालकों पर कार्रवाई की जरूरत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा में छोटी तकनीकी खराबी भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। इसलिए जिलेभर में संचालित सभी सरकारी और निजी एंबुलेंस का औचक निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी है।

ग्वालियर, जबलपुर समेत एक दर्जन कलेक्टरों के होंगे तबादले

मुख्यमंत्री की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को हरी झंडी

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में अगले कुछ दिनों के भीतर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष समेत शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही विभाग अफसरों के भी तबादले की तैयारी है। प्रशासनिक फेरबदल में ग्वालियर, जबलपुर, नीमच, शाजापुर कलेक्टर बदले जा सकते हैं। साथ ही चंबल, ग्वालियर एवं जबलपुर संभाग में भी नए आयुक्त पदस्थ किए जा सकते हैं।

मंत्रालय सूचों के अनुसार प्रशासनिक अफसरों की तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मुख्य सचिव के बीच चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने तबादला सूची को मंजूरी दे दी है। कुछ संशाधन के बाद तबादला सूची संभवत: अगले कुछ दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगा। बताया गया कि चंबल संभागायुक्त सुरेश कुमार पिछले महीने सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिलहाल ग्वालियर संभागायुक्त मनोज खत्री के पास प्रभार है। तबादला सूची में दोनों संभागों में नए कमिश्नर की पदस्थापना हो सकती है। इसी तरह जबलपुर संभागायुक्त भी बदले जा सकते हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले जाना हैं, उनमें ग्वालियर, शाजापुर, रायसेन, खंडवा, बड़वानी, नीमच, सीहोर, टीकमगढ़, गुना, सतना समेत करीब एक दर्जन से ज्यादा जिले हैं। हालांकि तबादला आदेश अलग-अलग जारी हो सकते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा विभागाध्यक्षों को भी बदलने की संभावना है। जिसमें उद्योग, पीएचई विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष शामिल हैं। शासन स्तर पर कुछ सचिव, प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्तर के विभागों में तब्दीली की जाएगी।

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

नारेबाजी कर फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला

बुरहानपुर, (एजेंसी)। दिल्ली में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में बुरहानपुर जयस्तंभ चौराहा पर शहर जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओंने ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की हिरासत को लेकर विरोध जताया और केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी , प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के एंड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कार्रवाई के विरोध में बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।कांग्रेस शहर जिलाअध्यक्ष रिंकू टॉक ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को मानने को तैयार नहीं हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकतांत्रिक तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी के विरोध में कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया है। जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी। रिंकू टॉक ने कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और लोकतंत्र एवं मतदाताओं की आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। कांग्रेस मीडिया प्रभारी तफफजुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि राहुल गांधी की हिरासत लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े हैं और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। मतदाता सूची में एंड और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है और कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से जारी रखेगी। विरोध प्रदर्शन में ,रिंकु टाक, वाज़िद इक़बाल, फ़हीम हाशमी ,अकील औलिया, फरीद काज़ी मुज्जु मीर जावेद खान, सहित बड़ी संख्यामें कांग्रेस जन उपस्थित हुए।

फरार आरोपितों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने घोषित किया इनाम

जबलपुर, (एजेंसी)। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने अलग-अलग मामलों में इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्तिको निर्धारित राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

भाजपा में अपने ही नेताओं के तेवर बने चुनौती

संघटन के अनुशासन पर भारी पड़ रहा स्थानीय असंतोष, बिप्लब देव की सख्ती के बाद भी थम नहीं रही बयानबाजी और विरोध

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन के स्तर पर अनुशासन का संदेश लगातार दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर नेताओं के असंतोष और सार्वजनिक विरोध के मामले थमते